



दैनिक

FAC NEWS
फाइट अगैस्ट क्रिमिनल

फाइट अगैस्ट क्रिमिनल



वर्ष : १०

अंक: ९४

मुंबई, मंगलवार १८ अगस्त २०२६

RNI. No. : MAHHIN/2016/71734

पृष्ठ-४

मूल्य २/रु.

**बारिश में धंसा गंगा एक्सप्रेसवे,
सड़क पर हुआ 10 मीटर का गड्ढा**



उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक और देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शुमार गंगा एक्सप्रेसवे बारिश के चलते धंस गया है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस 594 किमी लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 36000 करोड़ से अधिक की लागत आई थी, लेकिन बारिश की शुरुआती फुहारों में ही इसकी क्वालिटी की पोल खुल गई है।

दरअसल, मेरठ से प्रयागराज जाने वाले रूट पर उन्नाव क्षेत्र के पास किलोमीटर संख्या 421 पर एक्सप्रेसवे की सड़क और साइड रेलिंग के पास करीब 10 मीटर लंबा गहरा गड्ढा हो गया। अचानक सड़क धंसने से वहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कार्यदायी संस्था और यूपीडा (UPEIDA) के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विभाग के अधिकारी बारिश के बीच ही आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर सड़क और रेलिंग की मरम्मत कराने के कार्य में जुट गए हैं।

**राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने लखीसराय मंदिर
भगदड़ को लेकर जताया गहरा शोक,
पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्ति की संवेदनाएं**



बिहार के लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में सोमवार को हुई भगदड़ की दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बिहार के लखीसराय जिले में भगदड़ की दुर्घटना में श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ।'

**बिहार सरकार ने 500 का
डस्टबिन 15490 में खरीदा !**

बिहार में राजनीतिक गलियारों से एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सरकार पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल हो रही जानकारी के अनुसार, राज्य में कथित तौर पर 500 रुपये मूल्य वाले डस्टबिन को 15,490 रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस खुलासे के बाद से प्रशासनिक महकमे और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।



पालकमंत्री पद की बाजी में भाजपा- शिवसेना की जीत, राष्ट्रवादी का गेम!

रायगढ़ में गोगावले की ताजपोशी, नाशिक में महाजन का दबदबा

■ **मो. सईद शेख**

मुंबई। महाराष्ट्र में पालकमंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान आखिरकार खत्म हो गई है, लेकिन इस फैसले ने महायुक्ति के भीतर शक्ति संतुलन की तस्वीर साफ कर दी है। रायगढ़ में लंबे समय से दावा ठोक रहे भरत गोगावले पालकमंत्री बन गए, जबकि नाशिक की कमान भाजपा के गिरिश महाजन को दोबारा सौंप दी गई। यानी रायगढ़ में शिंदे गुट ने अपनी ताकत दिखाई और नाशिक में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। सबसे बड़ा झटका राष्ट्रवादी कांग्रेस को लगा, जो दोनों महत्वपूर्ण जिलों में अपनी दावेदारी मजबूत नहीं कर सकी। रायगढ़ में भरत गोगावले लंबे समय से पालकमंत्री पद के लिए आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। अदिति तटकरे को पालकमंत्री बनाए जाने के बाद राष्ट्रवादी और शिंदे गुट के बीच विवाद बढ़ा और नियुक्ति पर रोक लगी। विधानसभा चुनाव के बाद दोनों खेमों की राजनीतिक खींचतान और तेज हुई। राष्ट्रवादी ने गोगावले के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती देने के लिए स्नेहल जगतप, सुधाकर घारे और भाई सुरवे जैसे स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ा। महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान सुशांत जाबरे और विकास गोगावले के समर्थकों के बीच हुआ विवाद भी इसी बढ़ते टकराव की एक कड़ी माना गया। 2026 के विधान परिषद चुनाव के दौरान दोनों खेमों ने अपने-अपने परिवार के लिए राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश की। सीट राष्ट्रवादी के खाते में जाने के बाद गोगावले ने स्थानीय राजनीति पर अपना दबाव और बढ़ाया। उन्होंने लगातार यह संदेश दिया कि रायगढ़ में उन्हें नजरअंदाज करना महायुक्ति के लिए राजनीतिक रूप से महंगा पड़ सकता है। विधान परिषद की राजनीति में



पीछे हटने, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में सक्रियता और एकनाथ शिंदे के समर्थन ने आखिरकार उनका रास्ता साफ कर दिया। तटकरे खेमे को विधान परिषद की सीट मिलने के बाद पालकमंत्री पद पर समझौता

वह भी हाथ से निकल गया। नाशिक का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि अगले वर्ष कुंभ मेले की तैयारियां शुरू होनी हैं और महाजन के पास पहले से ही कुंभ से जुड़ी जिम्मेदारी है। पिछले कुछ महीनों में महाजन को लेकर कई विवाद और आरोप सामने आए, फिर भी भाजपा नेतृत्व ने उन पर भरोसा कायम रखा। दूसरी ओर छगन भुजबळ के साथ-साथ दादा भुसे की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुईं। लोकसभा से लेकर विधान परिषद और स्थानीय निकायों तक भाजपा-शिंदे गुट के बीच खींचतान के बावजूद अंत में भाजपा ने नाशिक अपने पास रखा। पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रवादी की राजनीतिक सौदेबाजी को लेकर है। रायगढ़ में गोगावले ने लगातार दबाव बनाया और एकनाथ शिंदे ने उनके साथ खड़े रहकर अपना जिला सुरक्षित कर लिया। 12 अगस्त की रात शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात में भी पालकमंत्री पद पर चर्चा की खबरें सामने आई थीं। दूसरी ओर राष्ट्रवादी नाशिक के लिए वैसा दबाव नहीं बना सकी। उसके पास छगन भुजबळ जैसा वरिष्ठ नेता होने के बावजूद पार्टी नेतृत्व न तो भाजपा को पीछे हटाने में सफल रहा और न ही पालकमंत्री पद हासिल कर सका। यही वजह है कि पालकमंत्री पद का यह फैसला सिर्फ दो जिलों की जिम्मेदारी का बंटवारा नहीं, बल्कि महायुक्ति के भीतर बदलते शक्ति समीकरण का संकेत माना जा रहा है। रायगढ़ में गोगावले की जिद और शिंदे की ताकत काम आई, नाशिक में फडणवीस के भरोसे ने महाजन को फिर मजबूत किया, लेकिन इन दोनों फैसलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में आया सिर्फ राजनीतिक झटका।

केतन अग्रवाल हत्याकांड में सच्चाई सामने लाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग

पुणे. केतन अग्रवाल हत्याकांड को दो महीने पूरे होने के बावजूद परिवार को अब तक न्याय नहीं मिलने का आरोप ल गाते हुए गुलाबो गैंग की ओर से आज सालासर डिस्ट्रीब्यूटर नरेंद्र मित्तल के फूफा की दुकान के सामने जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर पूरी सच्चाई सामने लाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। गुलाबो गैंग का आरोप है कि सिया को उसकी आत्मा और फूफा की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिली हो सकती है और उसे कानूनी अथवा अन्य तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग आंदोलनकारियों ने की है। साथ ही पूरे मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका रही है या नहीं, इसकी भी गहन जांच करने की मांग की गई।

आंदोलनकारियों ने विशेष रूप से सिया की आत्मा और नरेंद्र मित्तल की भूमिका की जांच करने तथा मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क, गतिविधियों और संभावित भूमिका की जांच कानून के दायरे में करने की मांग की। इस दौरान गुलाबो गैंग की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए 'केतन को न्याय मिलना ही चाहिए', 'हत्याकांड के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करो', 'दोषियों को कानून के अनुसार सजा दो' और 'केतन के परिवार को न्याय दो' जैसे नारे लगाए। विरोध के प्रतीक के रूप में सिया की प्रतिकृति बनाकर उस पर जूते मारकर भी आक्रोश व्यक्त किया गया। गुलाबो गैंग ने मांग की कि केतन अग्रवाल हत्याकांड की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच की जाए तथा सिया गोयल और अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जल्द से जल्द किया गया।



फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी की जाए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, आर्थिक लेन-देन और अन्य संबंधित साक्ष्यों की गहन जांच करने तथा किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक दबाव में आए बिना जांच पूरी करने की मांग की गई। गुलाबो गैंग की अध्यक्षता संगीता तिवारी ने कहा कि केतन अग्रवाल को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मामले का पूरा सच सामने आना चाहिए और दोषी कोई भी हो, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन में संगीता तिवारी, सोनिया ओझा, शोभा पणीकर, सुवर्णा माने, सीमा महाडिक, सुनीता नेमूर और प्रेमा पाटोके सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुईं।

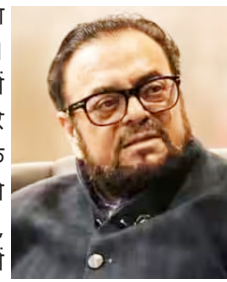
'आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कश्मीर में आतंक, पिछले साल मारे गए 26 लोग', अबू आजमी बोले- देश में विकास और भाईचारे की जरूरत

मुंबई: महाराष्ट्र में समाजवादी उस समय पाकिस्तान की तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक से कबायली ताकतों ने कश्मीर पर अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में विकास और भाईचारे की जरूरत है, न कि विभाजन की। उन्होंने आर्टिकल 370, केरल में राष्ट्रगान विवाद, वंदे मातरम, शहरों के नाम बदलने और नफरत की राजनीति जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की।

आर्टिकल 370 पर क्या बोले अबू आजमी?

अबू आजमी ने आर्टिकल 370 पर कहा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उम्मीद थी कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा। बातचीत हुई, लेकिन

उस समय पाकिस्तान की तरफ से कबायली ताकतों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर को मदद की जरूरत थी, इसलिए वहां के नेताओं ने मदद के लिए भारतीय नेतृत्व से संपर्क किया। भारतीय नेताओं ने कश्मीर को सुरक्षा और सैन्य मदद दी। हालांकि, इसमें एक शर्त भी शामिल थी, उसमें आर्टिकल 370 की भी बात थी, इसलिए ये लागू हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि तय हुआ था कि जब विधानसभा रहेगी और वहां से आर्टिकल 370 हटाने का बिल पास हो जाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा। सरकार ने 370 हटने के बाद घाटी से आतंकवाद खत्म होने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।



तीन साल से फरार दाऊद इब्राहिम का करीबी अख्तर मर्चेंट दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोचा गया

काशीमीरा बेकरी फायरिंग मामले में NBW और Red Corner Notice जारी था; 22 अगस्त तक ट्रांजिट रिमांड

नजमुल हसन रिजवी

मीरा भायंदर: मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी बताए जा रहे अख्तर मर्चेंट को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उसे 2023 के बहुचर्चित काशीमीरा बेकरी फायरिंग मामले में करीब तीन साल से फरार अख्तर कासमअली मर्चेंट को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पहले से गैर-जमानती वारंट (NBW) और रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी था। पुलिस अब उसके कथित अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, फायरिंग की साजिश और अन्य आरोपियों से संबंधों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को दोपहर 12.24 बजे मर्चेंट को IGI एयरपोर्ट पर इंटरसेप्ट कर हिरासत में लिया गया। उसी दिन उसे पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच के API योगेश काळे की मांग पर अदालत ने पांच दिन का ट्रांजिट रिमांड, यानी आरोपी को संबंधित अदालत तक ले जाने की न्यायिक अनुमति,

संजूर की। उसे 22 अगस्त तक ठाणे स्थित विशेष MCOCA न्यायालय के



समक्ष पेश किया जाना है।

2023 में बेकरी पर फायरिंग का मामला: 13 अक्टूबर 2023 को सुबह

करीब 10.09 बजे मीरा रोड पूर्व स्थित छत्रपती शिवाजी महाराज के पुतले के पास इंटरनैशनल बैंकिंग कंपनी में पिसतौल से फायरिंग के प्रयास की घटना हुई थी। CCTV फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ी और पुलिस को अख्तर मर्चेंट की कथित भूमिका का पता चला। काशीमीरा पुलिस थाने में दर्ज मामले में IPC की धारा 307, 381, 386, 120(B), 34, आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 तथा MCOCA की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में आरोपी पप्पू पेजर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। **विदेश में छिपे होने की मिली थी जानकारी:** पुलिस के मुताबिक, इंटरपोल इनपुट के आधार पर मर्चेंट के विदेश में होने की जानकारी मिली थी और उसके भारत लौटने पर निगरानी रखी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार, वह केन्या से नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया।

कारोबारी संबंधों को लेकर भी जांच: सूत्रों के अनुसार, बेकरी फायरिंग की

घटना से पहले अख्तर मर्चेंट कथित तौर पर गुटखा कारोबारी बाबू और पापा के साथ कारोबारी साझेदारी में काम करता था। सूत्रों का दावा है कि काशीमीरा क्षेत्र में उसे एक दुकान और एक फ्लैट भी दिया गया था तथा कथित तौर पर हर महीने एक निश्चित राशि 'सिक्वोरिटी अमाउंट' के रूप में ली जाती थी। इसी दौरान पप्पू पेजर की कथित एंटी होने की बात भी सामने आ रही है। मर्चेंट के कथित D-Company कनेक्शन और फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वह तीन वर्षों तक कहाँ रहा, किन लोगों के संपर्क में था और काशीमीरा फायरिंग मामले में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी। आरोपी को महाराष्ट्र लाने के बाद MCOCA अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कथित रंगदारी, अपराधिक साजिश और अन्य संभावित सहयोगियों को लेकर उससे विस्तृत पूछाछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी काशीमीरा फायरिंग मामले की जांच में क्राइम ब्रांच की महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।

संपादकीय



सुरक्षित हो डिजिटल वर्ल्ड, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अमेरिकी अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेंट कंपनी पर 5000 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म में बदलाव करने के लिए कहा है।

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर अमेरिका की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेंट कंपनी मेंटा पर करीब 5,390 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने पिछले साल 60 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। ऐसे में जुर्माने की रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण अदालत का यह आदेश है कि कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने प्लेटफॉर्म में बदलाव करने होंगे।

नाकाम रही कंपनी। न्यू मेक्सिको की अदालत ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इन प्लेटफॉर्म को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन शू किया गया है कि बच्चों को इसकी लत लग जाए। नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में भी कंपनी नाकाम रही है।

US में लगा जुर्माना। की रकम का एक हिस्सा पीड़ितों पर खर्च करने का आदेश दिया है, जो बताता है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। उनकी वजह से समाज में जो परेशानी शुरू हुई है, उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। किसी सोशल मीडिया कंपनी को पहली बार इस तरह कटघरे में खड़ा होना पड़ा है और मेंटा के लिए परेशानी की बात यह है कि अमेरिका के कई और राज्यों में भी इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इससे पहले मार्च में भी मेंटा पर 3500 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगा था।

गैर-कानूनी कंटेंट। पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि बच्चों को किस हद तक सोशल मीडिया इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए। कई देशों ने अपने यहां निश्चित उम्र सीमा भी लागू की है। हालांकि इसके साथ जरूरी मुद्दा यह भी है कि सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। भारत में भी मेंटा लगातार विवादों में है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को फेसबुक से हटाए जाने पर उसने माफी मांग ली।

यह तकनीकी गलती हो सकती है, पर पेड प्रमोशन के जरिये गैर-कानूनी कंटेंट को बढ़ावा देने की बात उसने खुद मानी है। इस साल जुलाई में केंद्र ने नोटिस भी जारी किया था।

बैन उपाय नहीं। अमेरिकी अदालत ने अगले पांच बरसों में मेंटा को कई सुरक्षा उपाय अपनाने का आदेश दिया है। इस तरह के कदम बाकी जगहों पर भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया किसी एक देश तक सीमित नहीं रही। हालांकि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी तरह बैन उपाय नहीं है, जरूरत जवाबदेही और नियंत्रण की है। का प्रश्न है तो तीनों हस्ताक्षरकर्ता देश एक-दूसरे की सैन्य एवं आर्थिक ताकतों को परस्पर क्षमताओं से संतुलित करते हैं। सऊदी अरब की शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा प्रभाव और भौगोलिक स्थिति है तो तुर्किये की ताकत उसकी नाटो सदस्यता एवं निरंतर उन्नत हो रहा रक्षा उद्योग है, जबकि पाकिस्तान के साथ भारी-भरकम सैन्य बल, परमाणु क्षमता और खाड़ी देशों में दीर्घकालिक सैन्य प्रशिक्षण एवं सुरक्षा सहयोग के अनुभव जैसे पहलु जुड़े हुए हैं।

मीरा रोड में स्कूल वैन पर गिरा मेट्रो का स्लैब, बाल-बाल बचे 8-9 विद्यार्थी

टुंगा अस्पताल के पास हादसे से मेट्रो निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल; FIR और सख्त कार्रवाई की मांग

नजमूल हसन रिजवी

मीरा रोड: मीरा रोड में टुंगा अस्पताल के पास सोमवार को मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। निर्माणाधीन मेट्रो के स्लैब का एक हिस्सा टूटकर नीचे सड़क पर जा गिरा और उसके पत्थर के टुकड़े वहां से गुजर रही स्कूल वैन पर जा गिरे। वैन में करीब 8 से 9 स्कूली विद्यार्थी सवार थे। गनीमत रही कि किसी भी विद्यार्थी को गंभीर चोट नहीं आई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्लैब का हिस्सा गिरने के बाद उसके टुकड़े स्कूल वैन से टकराए, जिससे वाहन का टायर पंचर हो गया। अचानक हुए इस हादसे से वाहन चालक और विद्यार्थियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, बड़ा हादसा टल गया और सभी विद्यार्थी सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

यह घटना दहिसर-मीरा भायंदर मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। व्यस्त सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन और स्कूली बच्चे गुजरते हैं, ऐसे में ऊंचाई पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।

जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के फाउंडर एवं अध्यक्ष प्रदीप जंगम ने इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मेट्रो का काम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।

जंगम ने आरोप लगाया कि मेट्रो परियोजना के दौरान कथित लापरवाही के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि MMRDA द्वारा J. Kumar कंपनी

पर पहले भी लापरवाही के लिए कई बार जुर्माना लगाया जा



चुका है, इसके बावजूद निर्माण कार्य में सुरक्षा संबंधी कथित चूक जारी है।

उन्होंने दावा किया कि मेट्रो-9 का काम शुरू होने के बाद अलग-अलग हादसों में करीब पांच लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उनके अनुसार, बिना पर्याप्त ट्रैफिक नियंत्रण के वेल्डिंग कार्य, क्रेन और भारी मशीनरी का इस्तेमाल तथा निर्माण सामग्री के गिरने जैसी घटनाओं ने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

प्रदीप जंगम ने मांग की कि मेट्रो निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों की कड़ाई से समीक्षा की जाए, सड़क से गुजरने वाले नागरिकों और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा जालियां एवं संरक्षक व्यवस्था अनिवार्य की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

फिलहाल इस घटना में किसी विद्यार्थी के घायल नहीं होने से राहत है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है? मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण

परियोजना के साथ विकास जरूरी है, लेकिन नागरिकों की



जान की कीमत पर नहीं।

MMRDA की सफाई: स्कूल वैन से नहीं टकराए पत्थर, 12.5 करोड़ का जुर्माना लगाया
मेट्रो-9 के मेदतिया नगर स्टेशन पर हुई घटना को लेकर MMRDA ने स्पष्ट किया है कि ग्रेनाइट के पत्थर किसी स्कूल वैन या बस पर नहीं गिरे और न ही किसी विद्यार्थी को चोट लगी। लगभग 11:50 बजे मलबा हटाने और सामग्री स्थानांतरित करने के दौरान क्रेन की मटेरियल बास्केट पास में रखे ग्रेनाइट पत्थरों से टकरा गई। कुछ पत्थर बैरिकेड वाले कार्यक्षेत्र में गिरे, जिन्हें बाद में वहां से गुजर रहे एक वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसके टायर पंचर हो गए। सुरक्षा चूक पर MMRDA ने J. Kumar पर ₹10 करोड़, गजानन पर ₹1.5 करोड़ और Systra-CEG-General Consultant पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

एक्ता मंच द्वारा आसाम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सी.डब्ल्यू.सी. कॉलेज में विशेष कार्यक्रम किया गया।



संवाददाता शोएब म्यानुंर मुंबई

मुंबई : वर्सावा स्थिति सी डब्ल्यू सी कोलेज के प्रिंसिपल अजय कॉल मार्गदर्शन में के एक्ता मंच की और से आसाम के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तारीख 17 अगस्त 2026 को डब्ल्यू सी कोलेज में किया गया।

आसाम के 1500 परिवार के लिए एक कीट भेजा जा रहा है। जिसमें राशन कीट, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी, मग, जैसे अनेकों आयटम दी जा रही है। टोटल केश रकम 21,87,823/- भी जमा हुआ है वो भी दिया जाएगा।

इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता, वर्सावा पुलिस स्टेशन सिनियर पी आई, और वर्सावा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य आसाम में बाढ़ से प्रभावित लोगों

के प्रति एकजुटता व्यक्त करना तथा उनके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल अजय कॉल, एक्ता मंच के पदाधिकारी, शिक्षकगण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय जरूरतमंदों की मदद करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आसाम के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सभी लोगों से आगे आने और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने की अपील की गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र पुनर्वास और सामान्य जनजीवन की बहाली की कामना की। कार्यक्रम का समापन मानवता और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए किया गया।



JANSEVA SOCIAL FOUNDATION
Non Government Organization
Reg. No. F-75914

NITI AYOGE 12A, 80G & CSR Registered

DONATE FOR POOR AND UNDERPRIVILEGED

Contact us 9930026943

SBI BANK JANSEVA SOCIAL FOUNDATION
Account No.: 39171751769
IFS Code : SBIN0012959
www.jansevasocialfoundation.com

701/ C Wing crystal Plaza opposite infinity mall Andheri West

‘वैनिटी में जाकर ये लगा दो, वो लगा दो’

संजीदा शेख इन दिनों अपनी खूबसूरती या ग्लैमरस लुक से नहीं, बल्कि दमदार किरदारों को लेकर अपनी बेबाक सोच से सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री ने साफ कर दिया है कि अब उनका फोकस घंटों मेकअप कराने और सिर्फ खूबसूरत दिखने पर नहीं, बल्कि कैमरे के सामने अपनी अदाकारी का दम दिखाने पर है। उनका कहना है कि टीवी के दौर में जरूरत से ज्यादा मेकअप के चलते कई बार उनका असली चेहरा तक नजर नहीं आता था। अब वह अपने लुक को नेचुरल रखते हुए किरदार को प्राथमिकता देती हैं। संजीदा के मुताबिक, हर किरदार की अपनी जरूरत होती है। अभिनेत्री का फंडा बिल्कुल साफ है कि वैनिटी वैन में ‘ये लगा दो, वो लगा दो’ से ज्यादा जरूरी है पर्दे पर ऐसी परफॉर्मेंस देना, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएं।



बारिश की वजह से समय से पहले खत्म हुआ तीसरे दिन का खेल, भारत 178 रन से आगे

तीसरे और आखिरी सेशन का खेल होने तक कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा खत्म हो गया है। सेशन के आखिरी में नाबाद रहे। जैसे ही श्रीलंका बैटिंग करने की श्रीलंका की टीम 284 रन पर ढेर हो गई।

आज भारत और श्रीलंका के बीच गॉल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक, टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। इस पारी में देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए और केएल राहुल ने 82 रन बनाए, तो वहीं ध्रुव जुरेल ने भी 51 रन बनाए।

बॉलिंग में, श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट लिए, जबकि केशरा नुवांथा ने 3 विकेट लिए। दूसरे दिन का खेल खत्म

होने तक कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद रहे। जैसे ही श्रीलंका बैटिंग करने की



तैयारी करेगा, मेजबान टीम को भारतीय बॉलिंग अटैक के सामने कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

15 अगस्त से CJP के देशव्यापी अभियान के बीच सरकारी स्कूलों में 'नो एंट्री'!

मीडिया पर सख्ती, क्या सरकारी स्कूलों की हकीकत सामने आने से डर रही सरकार?

जयपुर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से कॉकरोच जनता पार्टी (पण्ड) की ओर से देशभर के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाने के लिए अभियान शुरू किए जाने के बीच राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का नया आदेश कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर पण्ड के देशव्यापी अभियान के एलान के बाद राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में बिना पूर्व अनुमति बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का असर मीडिया की स्कूलों तक पहुंच पर भी पड़ सकता है। साथ ही विद्यार्थियों की फोटो और वीडियोग्राफी को लेकर भी शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकारी इच्छुटी पर आने वाले अधिकृत अधिकारियों को इसका अपवाद रखा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), POCSO एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम समेत अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता निश्चित रूप से गंभीर विषय है। नाबालिग बच्चों की तस्वीरों और वीडियो के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नियम और निगरानी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने

के साथ सरकारी स्कूलों की पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी को कैसे कायम रखा जाएगा। सरकारी स्कूल किसी निजी संस्था की संपत्ति नहीं हैं। इनका संचालन जनता के टैक्स और सरकारी बजट से होता



है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों की मौजूदगी, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, भोजन, पेयजल, शौचालय, भवनों की हालत और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानना भी जनता का अधिकार है। पण्ड ने 15 अगस्त से देशभर में सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाने का अभियान

चलाने का एलान किया है। अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और वास्तविक स्थिति को देश के सामने रखने की बात कही गई है। इसी बीच राजस्थान में बाहरी लोगों के प्रवेश और विद्यार्थियों की फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर सख्त आदेश सामने आने से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह महज बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा सामान्य प्रशासनिक फैसला है या CJP के अभियान के बाद सरकार भी इस बात को लेकर सतर्क हो गई है कि सरकारी स्कूलों की जमीनी तस्वीर देश के सामने न आए? अगर सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं सरकार के दावों के मुताबिक बेहतर हैं तो स्वतंत्र निरीक्षण और मीडिया की पड़ताल से डरने की वजह क्या है? किसी स्कूल की कमी सामने आती है तो वह सरकार के लिए उसे सुधारने का अवसर होना चाहिए। लेकिन अगर स्कूलों तक पहुंच ही सीमित कर दी जाए तो फिर जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकारी दावों और जमीन की हकीकत में कितना अंतर है? सरकार एक ओर सरकारी स्कूलों में सुधार, बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर मीडिया और अन्य बाहरी लोगों के प्रवेश को अनुमति से जोड़ने वाले आदेश ने पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है। बच्चों की पहचान और निजता की रक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्कूल की व्यवस्था, भवन, शौचालय, पेयजल, भोजन, शिक्षकों की उपस्थिति और सरकारी योजनाओं की स्थिति की स्वतंत्र रिपोर्टिंग किस सीमा तक की जा सकेगी, यह स्पष्ट होना जरूरी है।

सवाल यह है-मीडिया को भी अनुमति की जरूरत क्यों?

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर मीडिया की स्वतंत्र पड़ताल को भी अनुमति की दीवार के पीछे खड़ा किया जाना चाहिए? जिस स्कूल की व्यवस्था की वास्तविकता सामने लानी हो, उसी स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान से पहले अनुमति लेना पत्रकारिता की स्वतंत्रता को किस हद तक प्रभावित करेगा? अगर स्कूलों में सब कुछ बेहतर है तो कैमरे और मीडिया की मौजूदगी से परेशानी क्यों होनी चाहिए? और अगर कहीं खामियां हैं तो उन्हें सामने आने से रोकने से क्या वे खामियां खत्म हो जाएंगी? 15 अगस्त से पण्ड के

देशव्यापी अभियान के एलान और उसके बाद राजस्थान में जारी इस आदेश ने सवाल और गहरा कर दिया है। क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था सख्त कर रही है या फिर सरकारी स्कूलों के ऐसे हाल जनता और मीडिया की नजरों से दूर रखना चाहती है, जिनसे सरकार के दावों की पोल खुल सकती है? अब शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि यह आदेश केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता तक सीमित है या सरकारी स्कूलों की स्वतंत्र निगरानी और मीडिया की पहुंच पर भी प्रभाव डालेगा। क्योंकि सरकारी स्कूल जनता के हैं और जनता को उनकी हकीकत जानने का पूरा अधिकार है।

अमरावती मनपा का 44वां वर्धापन दिवस बना यादगार; पूर्व महापौरों का सम्मान, नई इमारत की घोषणा



अमरावती। अमरावती महानगरपालिका का 44वां स्थापना दिवस इस बार यादों, सम्मान और विकास के नए संकल्प के साथ मनाया गया। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित समारोह की सबसे खास बात रही कि वर्ष 1992 से अब तक शहर की महापौर की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी पूर्व महापौरों का सम्मान किया गया। इस दौरान अमरावती के विकास की अब तक की यात्रा को याद करते हुए शहर के सामने मौजूद चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समारोह में विधायक सुलभा खोडके, विधायक संजय खोडके, विधायक प्रवीण पोटे, विधायक रवि राणा, महापौर श्रीचंद तेजवाणी, उपमहापौर सचिन भेंडे, मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदवाले और नेता प्रतिपक्ष विलास इंगोले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य उपस्थित रहे। पूर्व महापौरों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को याद करते हुए उनके योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय प्रभाकरराव सवालालखे सहित दिवंगत पूर्व महापौरों के परिवारों का भी सम्मान किया गया। समारोह में वक्ताओं ने बताया कि अलग-अलग कार्यकाल में शहर के विकास को अलग दिशा मिली। किसी के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे को गति मिली तो किसी ने स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, अध्ययन केंद्र,

सार्वजनिक परिवहन और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया। शहर में सिटी बस सेवा, भूमिगत सीवरज, अभ्यासिका, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकास प्रारूप और आधारभूत सुविधाओं जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्व महापौरों के कार्यकाल से जोड़ा गया। विधायक रवि राणा ने समारोह में अमरावती के भविष्य को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि महापौर श्रीचंद तेजवाणी के कार्यकाल में ही अमरावती महानगरपालिका की नई इमारत बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अमरावती और बडनेरा को एक साथ जोड़ते हुए महानगरपालिका के नाम में बडनेरा-अमरावती को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी कही। विधायक सुलभा खोडके ने शहर के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मनपा की स्कूलों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। मराठी, हिंदी और उर्दू माध्यम के साथ सीबीएसई पेटर्न की शिक्षा शुरू होने से विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। पुरानी मनपा स्कूलों के भवनों के विकास और डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। विधायक प्रवीण पोटे ने शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे के उचित प्रबंधन का



मुद्दा उठाया। उन्होंने व्यापारियों के लिए पर्याप्त घनकचरा पेटियां उपलब्ध कराने के लिए पालकमंत्री निधि से प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर के 16 पूर्व महापौरों ने अपने-अपने कार्यकाल में अमरावती के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कार्यों को याद रखना जरूरी है। समारोह में शहर के सौंदर्यीकरण, उद्यानों के विकास, वडाली झील और अन्य सार्वजनिक स्थलों के सुशोभीकरण, वृक्षारोपण, हरित पट्टियों, आकर्षक पथदिवे, सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, खेल सुविधाओं, अभ्यासिका और वाचनालय जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अमरावती को स्वच्छ, सुंदर, हरित और आधुनिक शहर बनाने के लिए विकास की गति को आगे भी कायम रखना जरूरी है। इस तरह अमरावती महानगरपालिका का 44वां स्थापना दिवस केवल औपचारिक समारोह बनकर नहीं रहा। पूर्व महापौरों के योगदान को सम्मान देकर जहां शहर के इतिहास को याद किया गया, वहीं नई मनपा इमारत, घनकचरा प्रबंधन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों ने अमरावती के भविष्य की विकास दिशा भी स्पष्ट कर दी। समारोह ने अतीत के सम्मान के साथ अमरावती के विकास के नए संकल्प की तस्वीर पेश की।

गांजा-गावठी शराब के खिलाफ बसपा का हल्लाबोल, अमरावती के यशोदा नगर में रास्ता रोको



अमरावती। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के यशोदा नगर चौक में नशे के कथित अवैध कारोबार और देसी शराब की दुकान के विरोध में सोमवार, 17 अगस्त को बसपा नगरसेवक सचिन वैद्य के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों ने क्षेत्र में गांजा और गांवठी शराब की कथित बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के साथ देसी शराब की दुकान हटाने की मांग की। आंदोलन की सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और नगरसेवक सचिन वैद्य, इस्माइल लालुवाले, नगरसेविका विद्या माटे सहित कुछ आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर देसी शराब की दुकान संचालित है, उसके आसपास स्कूल, बौद्ध विहार, शिव मंदिर और वाचनालय जैसे सार्वजनिक व धार्मिक स्थल मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि शराब की दुकान इन स्थलों से 100 मीटर के दायरे में है।

मुथूट फिनकोर्प गोल्ड लोन घोटाले में बड़ी बरामदगी, 1.260 किलो सोना जब्त

अमरावती। मुथूट फिनकोर्प की अमरावती शाखा में सामने आए बहुचर्चित गोल्ड लोन घोटाले की जांच में सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रविवार को शहर के एक सुनार के पास से 1 किलो 260 ग्राम सोना बरामद किया है। बरामद सोने की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, यह अब तक की जांच में सबसे बड़ी बरामदगी है और इससे घोटाले के नेटवर्क की कई अहम कड़ियां सामने आने की उम्मीद है। जांच में सामने आया है कि मुथूट फिनकोर्प में ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों का कथित



तौर पर उनकी जानकारी के बिना दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि शाखा के कुछ कर्मचारियों ने ग्राहकों का सोना शहर के विभिन्न सुनारों और अन्य माध्यमों से दोबारा गिरवी रखकर रकम जुटाई। मामले में अब तक पुलिस को करीब 60 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और घोटाले का दायरा कई करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। मामले की शुरुआत महाजनपुरा निवासी शालिनी काशीनाथ नागर गोजे की शिकायत से हुई। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने शाखा प्रबंधक शुभम रविंद्र वासेवा, कर्मचारी सुनील अनिल खैरकर और धीरज पंचमराव सिरसाट के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस ने दो सुनारों के पास से करीब 90 ग्राम सोना बरामद किया था। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के आधार पर शहर के अन्य सुनारों तक पुलिस पहुंची। इसी कड़ी में रविवार को एक सुनार के पास से 1.260 किलो सोना बरामद किया गया। पुलिस अब बरामद सोने की पहचान और उसके वास्तविक स्वामित्व की पुष्टि कर रही है। जांच में एक अन्य सुनार करुले का नाम भी सामने आया है, जिसके पास करीब 3 किलो सोना गिरवी रखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली है। घोटाला उजागर होने के बाद से करुले फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और उससे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ग्राहकों का कुल कितना सोना शाखा से बाहर गिरवी रखा गया, उससे कितनी रकम जुटाई गई और उस रकम का इस्तेमाल कहां किया गया। शाखा के अन्य कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं तथा उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जांच की जा रही है। 1.260 किलो सोने की बरामदगी के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। अब पुलिस की नजर फरार सुनार करुले और उसके पास बताए जा रहे करीब 3 किलो सोने पर टिकी है। उसकी गिरफ्तारी और बरामदगी से घोटाले के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका से पर्दा उठने की उम्मीद है।

बॉम्बे हाईकोर्ट टाइपिंग टेस्ट पर विवाद अभ्यर्थियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट में लिपिक पद के लिए आयोजित ऑ नलाइन टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई उम्मीदवारों को बिना गलती के असफल घोषित कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि टेस्ट के दौरान कंप्यूटर, सर्वर और कीबोर्ड से जुड़ी समस्याएं सामने आईं, जिससे उनकी टाइपिंग प्रभावित हुई। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के दौरान स्क्रीन में खराबी आई और कई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था का आरोप उम्मीदवारों के मुताबिक सुबह के सत्र में कई परीक्षार्थियों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने सर्वर रिसॉन्स

नहीं करने और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कत की शिकायत की। इसके बाद परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में हुई तकनीकी गड़बड़ी का असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा है, इसलिए सभी प्रभावित उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाना चाहिए। अभिजीत दीपके भी पहुंचे प्रदर्शन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी (कांजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके भी शामिल हुए। उन्होंने प्रभावित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। दीपके ने आरोप लगाया कि कई उम्मीदवारों को बिना किसी गलती के फेल कर दिया गया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वह उनके साथ खड़े रहेंगे। दोबारा परीक्षा की मांग प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तकनीकी समस्याओं से प्रभावित सभी उम्मीदवारों के लिए फिर से टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाए।

‘एक वृक्ष शहीद के नाम’ अभियान से बडनेरा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश

अमरावती। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद की ओर से बडनेरा स्थित आदिवासी वसतिगृह परिसर एवं मधुबन वृद्धाश्रम में राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। ‘एक वृक्ष शहीद के नाम, हरियाली से करें राष्ट्र को सलाम’ के संदेश के साथ आयोजित इस अभियान में शहीदों को वृक्षारोपण के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हौशीला प्रसाद दुबे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कुलदीप सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबाजी गोलदाज तथा महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष शरद भीमराव ठोसरे के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों, नागरिकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, पौधों के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित एवं स्वस्थ वातावरण निर्माण का संदेश



दिया गया। उपस्थित लोगों से ‘वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं और पर्यावरण की रक्षा करें’ का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बंडू धामणे, महिला सेल की चंदा सोनपराते, महिला सेल उपाध्यक्ष माया महाडीक, अमरावती अध्यक्ष नरेश धमाई, उपाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र ढोबले, नितीन मांजरे, अजय बेहरे, राजेश गव्हाले, रुपेश केंद्रेले, कपिल यादगरे, बडनेरा अध्यक्ष शंकरराव गव्हाले, कानून सलाहकार एड. शुभम खाजोने, समन्वयक दिनेश यादव सहित संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। बियाणी चौक अमरावती मॉनिंग ग्रुप के वरिष्ठ नागरिकों ने भी अभियान में सहभागिता की। आयोजकों ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान को याद करने का सबसे सार्थक तरीका प्रकृति की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से वृक्षारोपण अभियान को राष्ट्रीय और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया।

सीजेपी के बाद अब 'दिमागी नक्सल पार्टी' की डिजिटल दस्तक

24 घंटे में 1.9 लाख फॉलोअर्स; बड़े नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जुड़े

मुन्ना मुजावर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 'दिमागी नक्सल' शब्द के इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर इसी नाम से एक नया राजनीतिक डिजिटल कैम्पेन तेजी से उभर आया है। 'कों करोच जनता पार्टी' के बाद अब 'दिमागी नक्सल जनता पार्टी' और 'दिमागी नक्सल पार्टी' नाम से बनाए गए अकाउंट चर्चा में हैं। इनमें से एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज 24 घंटे में 1.9 लाख से अधिक फॉलोअर्स जोड़कर सोशल मीडिया की राजनीतिक दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। इस नए कैम्पेन का स्लोगन 'सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो' रखा गया है। कैम्पेन के जरिए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाने, जानकारी हासिल करने और विरोध की आवाज को डिजिटल मंच पर मजबूत करने का संदेश दिया जा रहा है। नाम सामने आने के साथ ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस, प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक्स पर ʘʘʘʘʘʘʘʘ नाम से मौजूद अकाउंट भी तेजी से चर्चा में आया है। यह अकाउंट कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी, कॉ मेडियन कुणाल कामरा और अभिनेता प्रकाश राज समेत कई चर्चित राजनीतिक नेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है। इस वजह से कैम्पेन की राजनीतिक दिशा को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संबंधित अकाउंट इसी महीने बनाया गया है और इसका यूजरनेम भी

एक बार बदला गया। अकाउंट पर अब तक 60 से अधिक पोस्ट सामने आ चुकी हैं और वह करीब 35 अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है। हालांकि, इस पूरे कैम्पेन को संचालित



कौन कर रहा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अकाउंट पर किसी व्यक्ति, समूह या आधिकारिक राजनीतिक संगठन के बारे में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसी नाम से इंस्टाग्राम पर कई अन्य अकाउंट भी दिखाई दे रहे हैं। कैम्पेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता है। शुरुआत के कुछ ही घंटों में इसके फॉलोअर्स हजारों में पहुंच गए और 24 घंटे के भीतर संख्या 1.9 लाख के पार बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक नाम या नारे का इतनी तेजी से लोकप्रिय होना

अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, 'दिमागी नक्सल' शब्द को लेकर राजनीतिक बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण के बाद शुरू हुई। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सशस्त्र नक्सलवाद के कमजोर पड़ने का जिक्र किया और देश को 'दिमागी नक्सलियों' से भी सतर्क रहने की बात कही। इसके बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पी. चिदंबरम समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी, जबकि केंद्रीय मंत्री किरें रिजिजू ने भी 'दिमागी नक्सल' की व्याख्या की। यहीं से प्रधानमंत्री के भाषण का एक शब्द सोशल मीडिया की नई राजनीतिक भाषा का हिस्सा बनता दिखाई दिया। जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने वैचारिक खतरे के संदर्भ में किया था, उसी को सोशल मीडिया पर एक नए राजनीतिक नाम और डिजिटल पहचान में बदल दिया गया। 'सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो' जैसे स्लोगन के साथ शुरू हुआ यह कैम्पेन अब महज एक सोशल मीडिया पेज तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि राजनीतिक बहस में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। फिलहाल 'दिमागी नक्सल पार्टी' किसी स्थापित राजनीतिक दल के रूप में सामने नहीं आई है और इसके संचालकों की पहचान भी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से इस नाम ने सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल की है, उसने राजनीतिक गलियारों में नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—क्या यह केवल एक वायरल डिजिटल कैम्पेन है या आने वाले दिनों में सोशल मीडिया की राजनीति में एक नई डिजिटल ताकत के रूप में उभरेगा?

रावेत में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना मेडिकल डिग्री मरीजों का कर रहा था इलाज

मुन्ना मुजावर

पिंपरी, 17 अगस्त 2026 : बिना किसी मान्य मेडिकल डिग्री और वैद्यकीय योग्यता के मरीजों का इलाज करने तथा उन्हें दवाइयां और इंजेक्शन देने वाले एक फर्जी डॉक्टर को रावेत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रविवार (16 अगस्त) की मध्यरात्रि करीब 12 बजे पांढरे वस्ती, पुनावळे क्षेत्र में की गई। आरोपी के खिलाफ मरीजों को गुमराह कर अवैध रूप से चिकित्सा सेवा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।



गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागवत टेटकुराम निषाद (उम्र 39 वर्ष, निवासी रावेत) के रूप में हुई है। इस मामले में पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नंदकुमार मोरे (उम्र 47 वर्ष, निवासी चिंचवड, पुणे) ने रावेत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रावेत पुलिस के पुलिस उपनिरीक्षक राहुल खिळे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पांढरे वस्ती, पुनावळे परिसर में एक व्यक्ति के पास किसी प्रकार की वैद्यकीय डिग्री या आवश्यक चिकित्सा योग्यता नहीं होने के बावजूद वह नागरिकों को दवाइयां और इंजेक्शन देकर उनका इलाज कर रहा था। इसकी जानकारी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के वैद्यकीय विभाग को मिली थी। जानकारी मिलने के बाद वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नंदकुमार मोरे के नेतृत्व में संबंधित टीम ने मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान भागवत निषाद मरीजों की जांच करते हुए पाया गया। वह दवाइयां और इंजेक्शनों की बिक्री करने के साथ-साथ मरीजों को चिकित्सा उपचार भी दे रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी के पास मरीजों का इलाज करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय अर्हता नहीं थी। इसके बावजूद वह अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा था और मरीजों को उपचार के नाम पर गुमराह कर रहा था। बताया गया है कि आरोपी केवल एक स्थान पर ही नहीं, बल्कि घरों-घरों जाकर भी मरीजों का इलाज करता था और उन्हें दवाइयां तथा इंजेक्शन देता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रावेत पुलिस ने आरोपी भागवत निषाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 319(2) तथा महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसायी अधिनियम, 1961 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

कुश्ती क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रा. वसंतराव पाटील सम्मानित

‘यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय पुरस्कार-2026’ से बढ़ा मीरा भायंदर का गौरव

अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

मीरा भायंदर कुश्तीगीर संघ संचालित श्री गणेश



नजमुल हसन रिज़वी मीरा भायंदर: कुश्ती क्षेत्र में दशकों से उल्लेखनीय एवं निःस्वार्थ योगदान देने वाले वरिष्ठ कुश्ती संगठक एवं प्रशिक्षक प्रा. वसंतराव यशवंत पाटील को प्रतिष्ठित 'यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय पुरस्कार-2026' से सम्मानित किया गया।

यशवंतराव चव्हाण फाउंडेशन, मुंबई की ओर से यह पुरस्कार 15 अगस्त 2026 को नवी मुंबई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वाशी में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता ठाणे जिला सूचना अधिकारी मनोज सुमन शिवाजी सावंत ने की। उनके हाथों प्रा. पाटील को सम्मानचिह्न प्रदान कर गौरवान्वित किया गया। इस अवसर पर नवी मुंबई मनपा नगरसेवक नमित विजय चौगुले तथा शिवसेना नवी मुंबई के उपजिलाप्रमुख चंद्रकांत चाळके सहित

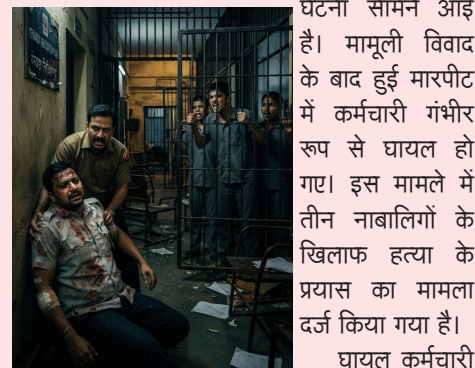
आखाड़ा, भायंदर के मार्गदर्शक प्रा. पाटील ने कुश्ती प्रशिक्षण, युवा विकास, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके मार्गदर्शन में अनेक मल्लों ने राज्य, राष्ट्रीय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर सफलता हासिल की है।

इस सम्मान से आखाड़ा परिवार, खिलाड़ियों और अभिभावकों में हर्ष एवं गर्व का वातावरण रहा। इसे प्रा. पाटील के साथ श्री गणेश आखाड़े की संस्कारक्षम परंपरा का भी सम्मान बताया गया।

येरवडा निरीक्षणगृह में कर्मचारी पर नाबालिगों का हमला, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

मुन्ना मुजावर

पुणे : येरवडा स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र (बाल शासकीय निरीक्षणगृह) में एक कर्मचारी पर तीन नाबालिगों द्वारा हमला किए जाने की गंभीर



घटना सामने आई है। मामूली विवाद के बाद हुई मारपीट में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में तीन नाबालिगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। घायल कर्मचारी की पहचान संतोष किसन कुंभार (उम्र 50 वर्ष, निवासी नंददीप सोसायटी, चन्होली फाटा) के रूप में हुई है। इस संबंध में कुंभार ने येरवडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, रविवार 16 अगस्त को सुबह करीब 10:30 बजे संतोष कुंभार निरीक्षणगृह में रह रहे नाबालिगों को नाश्ता वितरित कर रहे थे। इसी दौरान मामूली विवाद को लेकर तीन नाबालिगों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में कुंभार गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त सुनील जैतापूरकर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश गिते ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक देठे कर रहे हैं। गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए गए नाबालिगों को बाल न्याय मंडल के आदेश के बाद येरवडा स्थित पं. जवाहरलाल नेहरू उद्योग केंद्र में रखा जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मामूली विवादों को लेकर निरीक्षणगृह में नाबालिगों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा निरीक्षणगृह से नाबालिगों के फरार होने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस ताजा घटना के बाद निरीक्षणगृह की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

मीरा भायंदर कांग्रेस में नई जिला कार्यकारिणी घोषित, 43 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी

बंडखोरों और पदलोलुपों को किनारे रख संगठन सुदृढ़ीकरण पर जोर

नजमुल हसन रिज़वी

मीरा भायंदर:

मीरा भायंदर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा कर दी है। जिला अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित के नेतृत्व में कुल 43 पदाधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी ने संगठन विस्तार के तहत कई समुदाय-विशेष प्रकोष्ठों का भी गठन किया है, जिनमें सिख, राजस्थानी, ओडिशा, उत्तर भारतीय और डॉक्टर्स सेल प्रमुख हैं। इन प्रकोष्ठों के माध्यम से कांग्रेस ने समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति अपनाई है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य मुजफ्फर हुसैन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों का खुलकर विरोध किया जाए तथा कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएं।

जिला अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित ने स्पष्ट किया कि यह पुनर्गठन केवल पद वितरण नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी और जनसमस्याओं पर संघर्ष को और तेज करेगी।

नई नियुक्तियों में दीपक बागड़ी को जिला सोशल मीडिया अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रवि खरात को यूथ कांग्रेस एवं बेसिक विंग का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस



नगरसेविका रिज़वाना खान के पति अनवर खान को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है।

हालांकि, इससे पहले हुई नियुक्तियों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष भी उभरकर सामने आया था। विशेषकर उन नेताओं को

लेकर सवाल उठ रहे थे जिन्होंने मीरा भायंदर महानगरपालिका चुनावों के दौरान पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, या बगावत के डर से उन्हें पद दिया गया था। संगठन के भीतर यह चर्चा तेज है कि चुनाव के बाद लौटे कुछ नेताओं को पद देकर पुरस्कृत किया गया, जबकि निर्दलीय या बागी होकर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों से दूर रखा गया है। इस घटनाक्रम ने संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच आंतरिक असंतोष की स्थिति भी पैदा कर दी थी, जबकि पार्टी इसे राजनीतिक मुकाबले से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद बता रही थी। हालांकि, सूत्रों का मानना है कि पार्टी ने गलती सुधारकर उन लोगों को आराम दे दिया है।

घोषणा के दौरान विपक्ष नेता आफरीन सय्यद, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद सामंत, कई पूर्व नगरसेवक, वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नई टीम के गठन के साथ कांग्रेस ने मीरा भायंदर में संगठन को नई गति देने का प्रयास किया है, लेकिन बागियों और पदलोलुपों को किनारे रखकर यह टीम जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है, यह आने वाला समय तय करेगा।

RIGHT GUIDANCE LEADS TO SUCCESS

DILIP SIR'S KABIR CLASSES

CBSE - STATE BOARD - ICSE

SCHOOL SECTION

MATHS & SCIENCE

8th, 9th, 10th

COLLEGE 11th & 12th

PHYSICS

CHEMISTRY

MATHEMATICS

BIOLOGY

ADVANTAGE KABIR

- Small batches
- Personal attention
- Expert Excellent Experienced faculties for each subject
- Revision and Doubt solving sessions
- Regular Test series with tracking and analysis of performance
- Proven results

SCIENCE | COMMERCE | ARTS

MHT CET - NEET

Contact us

93240 59679

Visit us at

G-2 Mahesh tower, Pancham society, Gilbert Hill road, Andheri west Mumbai 400058.

पोदार इंटरनेशनल स्कूल, हडपसर में देशभक्ति के रंग में रंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह: 'भारत माता

मुन्ना मुजावर

हडपसर, पुणे : पोदार इंटरनेशनल स्कूल, हडपसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह, उमंग और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ भव्य रूप से मनाया गया। विद्यालय परिसर में चारों ओर तिरंगे की शान, देशभक्ति का जोश और विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राधिर सतीश जी एवं एसीपी अश्विनी शेंडगे जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों एवं प्रधानाचार्य महोदय के करकमलों से ध्वजारोहण किया

गया। तिरंगा शान से लहराते ही पूरा विद्यालय परिसर राष्ट्रगान की गूंज से भाव-विभोर हो उठा। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता के महत्व, देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, अनुशासन, ईमानदारी और समर्पण के साथ देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत, नृत्य, भाषण और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की जोशीली एवं मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का

मन मोह लिया। प्रत्येक प्रस्तुति में देश के प्रति प्रेम, शौर्य और एकता का संदेश दिखाई दिया। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की शानदार प्रस्तुतियों, आत्मविश्वास और प्रतिभा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं और उनमें राष्ट्रप्रेम, संस्कार तथा जिम्मेदारी की भावना विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। समारोह के समापन अवसर पर पूरा विद्यालय परिसर 'भारत माता की जय' और 'जय हिंद' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस का यह भव्य समारोह विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपस्थित सभी लोगों के लिए देशभक्ति, एकता और राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करने वाला यादगार अवसर बन गया।



यह दैनिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4- ग्राउंड फ्लोर, एन के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नीयर प्रवासी इंडस्ट्रियल इस्टेट, गेट नं. 2, गोगेगांव पूर्व, मुंबई 400 063 से छपवाकर, रुम नं. ३६१, जाकिर अली चॉल, स्कॉटर कॉलोनी, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०६० से प्रकाशित. संपादक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख मो.: ९९३००२६९४२ / ९९३००२६९४३ कार्यकारी संपादक - विक्रम सेन email -fightagainstcriminal2016@gmail.com RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 सभी पद अवैतनिक है, (विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा)